

तीसरी सीट के लिए भाजपा से महेश केवट ने भरा नामांकन

► सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सहित आधा मंडिमंडल भी रहा मौजूद

► तीसरी सीट के लिए भाजपा का बड़ा दांव

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 8 जून. राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए सोमवार को भाजपा ने भी ताल ठोक दी है. रविवार देर रात महेश केवट के नाम पर सहमति के बाद सोमवार दोपहर को केवट ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए दावेदारी जताते हुए नामांकन जमा कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ आधा मंडिमंडल भी इस दौरान मौजूद था, जो कि इस बाद का संकेत दे रहा था कि भाजपा तीसरी सीट जीतने के लिए भी गंभीर है.

राज्यसभा उम्मीदवार केवट की ओर से नामांकन के तीन सेट जमा किए गए. सभी सेट में विधानसभा के 10-10 सदस्य प्रस्तावक बने हैं. सोमवार को नामांकन भरने का अंतिम दिन था, अब 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, उम्मीदवार 11 जून तक नामांकन वापस ले सकेंगे. भाजपा के तीसरे उम्मीदवार की दावेदारी से अब तय हो गया है, कि 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश में



सीएम के साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचे केवट

राज्यसभा के लिए नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित ज्यादातर भाजपा के दिग्गज और मंत्री पहले भाजपा कार्यालय पहुंचें. यहां सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और केवट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर उसके बाद नामांकन जमा करने के लिए विधानसभा सचिवालय के लिए रवाना हुए. सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा उम्मीदवार महेश केवट सीएम डॉ. यादव के साथ ही उनकी कार में बैठकर विधानसभा परिसर पहुंचें, जहां विधानसभा के प्रमुख सचिव और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उन्होंने नामांकन भरा .

मतदान होगा. राज्यसभा की तीन सीटों के लिए कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया है. शनिवार को भाजपा की ओर से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने भी नामांकन भर दिया था. इस तरह तीन सीटों के लिए भाजपा की ओर से तीन उम्मीदवार और कांग्रेस की ओर से एक उम्मीदवार मैदान में हैं.

नामांकन भरने से पहले सबेरे बीना से विधायक निर्मला सप्रे सीएम हाउस पहुंचीं और

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की. इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल निर्मला सप्रे अभी तकनीकी रूप से कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का दामन थाम लिया था, निर्मला सप्रे ने अब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे समय जब कि तीसरी सीट के लिए भाजपा के लिए एक-एक वोट का महत्व बढ़ गया है, निर्मला

केवट ने मधुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

सोमवार को नामांकन भरने से पहले महेश केवट ने रविवार को ही मधुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. केवट को पिछले माह ही बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. केवट मूल रूप से बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले के ओरछा से आते हैं .

सप्रे का साथ भाजपा के लिए किसी राहत से कम नहीं है. सोमवार सबेरे ही मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित चुनिंदा पदाधिकारियों ने विधायकों को राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया की जानकारी साझा की.

मीनाक्षी के नामांकन में कांग्रेस एकजुट

विशेष संवाददाता भोपाल, 08 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया.

नटराजन ने विधानसभा परिसर में राज्यसभा निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. नामांकन दाखिल करने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी के साथ मीडिया को संबोधित किया. उमंग सिंधार ने कहा कि कांग्रेस के सभी



विधायक मीनाक्षी नटराजन के साथ विधानसभा पहुंचे हैं, जो पार्टी की एकजुटता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह केवल मीनाक्षी नटराजन की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की लड़ाई है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होगी. सिंधार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरे राज्यसभा

उम्मीदवार का नामांकन उसके वास्तविक चरित्र को उजागर करता है. यह संविधान की लड़ाई है और अंततः संविधान की जीत होगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी ने नटराजन को गांधीवादी मूल्यों से प्रेरित नेता बताते हुए कहा कि उनकी उम्मीदवारी महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का प्रतीक है.

कुएं में शव फेंककर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद

सिंगरौली. देवसर स्थित पंचम अपर सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवसागर उर्फ रिंकू बियार उम्र 25 वर्ष, अंशू बियार उम्र 26 वर्ष तथा उमेश उर्फ मुनेश कुमार बियार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गोंदवाली थाना बरगावां को हत्या और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी पाया. अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी के अनुसार घटना 5 जून 2022 से 7 जून 2022 के बीच की है.

कुएं में शव फेंककर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद

सिंगरौली, 8 जून. देवसर स्थित पंचम अपर सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवसागर उर्फ रिंकू बियार उम्र 25 वर्ष, अंशू बियार उम्र 26 वर्ष तथा उमेश उर्फ मुनेश कुमार बियार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गोंदवाली थाना बरगावां को हत्या और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी पाया. अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी के अनुसार घटना 5 जून 2022 से 7 जून 2022 के बीच की है.

आरोपियों ने मृतक सुरेश कुमार बैस उर्फ नारद की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत मृतक को उसके सिंचाई वाले कुएं के पास शराब पिलाई गई. इसके बाद रिंकू बियार ने उसके गले में रस्सी कस दी, जबकि अंशू बियार ने लोहे की रॉड से सिर व शरीर पर हमला किया. हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया. ग्रामीणों ने कुएं में शव तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने पक्ष रखा.

पटवारी 10 हजार की रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार



संबंधित पटवारी प्रवीण पाटीदार ने 10-10 हजार रुपए प्रति प्लॉट के हिसाब से 20 हजार रुपए की रिश्तत मांगी. तिवारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त इंदौर में की. सत्यापन में शिकायत सही

आयोजन

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आज विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर

समय पर जांच से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित : शुक्ल

भोपाल, 8 जून. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है. राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श एवं उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें.

उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच एवं उच्च जोखिम



स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे

दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात से किया इंकार, हाईकोर्ट ने मां बनने की दी अनुमति

जबलपुर. हाईकोर्ट के जस्टिस आरके वाणी की ग्रीष्म अवकाश कालीन पीठ ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता के मामले में संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे बच्चे को जन्म देने की अनुमति प्रदान कर दी है. साथ ही राज्य शासन को निर्देशित किया है कि नवजात के 16 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्च वहन किया जाए. न्यायालय ने उक्त आदेश खरगौन जिले के बालकवाड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े एक पाक्सो प्रकरण में पारित किया. गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक होने तथा पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मंडलेश्वर स्थित विशेष पाक्सो न्यायालय ने मार्गदर्शन हेतु प्रकरण हाईकोर्ट को प्रेषित किया था, जिस पर संज्ञान लेकर सुनवाई की गई.

गिरिबाला सिंह की बैरक की सुरक्षा प्रभारी को हटाया

नवभारत रिपोर्टर भोपाल, 08 जून. टिववरा शर्मा मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सेंट्रल जेल भोपाल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली महिला अधिकारी पर गाज गिर गई है. गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

जानकारी सामने आई है कि गिरिबाला की बैरक की सुरक्षा प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में हटाया गया है. जया के स्थान पर अब एक महिला मेडन (वार्डन) की नियुक्ति की गई है. जेल प्रशासन ने

मोदी के मंत्री ने ईई को जमकर फटकारा

घटिया निर्माण कार्य को लेकर जताई नाराजगी

टीकमगढ़, 08 जून.आमिर खान.लोक निर्माण विभाग के घटिया निर्माण कार्य को देख मोदी कैबिनेट के मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में लोक निर्माण विभाग के ईई को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं अटल सभागार का उद्घाटन करे बिना ही मंत्री जी वहां से नाराज होकर चल दिए.

दरअसल लिधौरा ताल में सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल सभागार का उद्घाटन करने पहुंचे. सभागार के घटिया निर्माण चटका फर्श और दीवार का काम को देखकर केंद्रीय मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और बिना फीता काटे ही वापस लौट गए. इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज दुबे को



घटिया निर्माण के लिए कड़ी फटकार लगाई. मंत्री ने विशेष रूप से सभागार में कोटा स्टोन की जगह सीमेंट फर्श लगाए जाने पर आपत्ति जताई, जो उद्घाटन से पहले ही कई जगह से उखड़ गया था. सभागार की सीढ़ियों की गुणवत्ता भी खराब पाई गई, जिनमें जगह-जगह दरारें आ गई थीं |यह अटल सभागार केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा सांसद और दीवार का काम को देखकर केंद्रीय मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और बिना फीता काटे ही वापस लौट गए. इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की और मेसर्स शर्मा एसोसिएट के

ठेकेदार सार्थक शर्मा ने इसका निर्माण कार्य किया था |केंद्रीय मंत्री ने सभागार में बैठकर पूजन तो किया, लेकिन उद्घाटन का फीता नहीं काटा.

उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी से कहा कि शासन की राशि का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. उन्हें स्वागत-सत्कार या फूलमालाओं की कोई चाह नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य ही उनका सच्चा सम्मान है. मंत्री ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सभागार के फर्श पर कोटा स्टोन बिछाने, सीढ़ियों में सुधार करने और समय गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए.

जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का आरोप

जेल के अंदर गिरिबाला और समर्थ को मिली रही सुविधाओं की कथित वीआईपी ट्रीटमेंट संबंधी जांच की रिपोर्ट को तैयार कर डीआईजी जेल ने जेल महानिदेशक को सौंपी है. सूत्र बता रहे हैं कि मामले में एक अन्य डिप्टी जेलर सहित दो अधिकारियों पर भी जेल प्रशासन जल्द ही एक्शन ले सकता है. बताया यह भी जा रहा है कि कथित वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायतों के जांच स्पष्ट होने पर गिरिबाला और समर्थ की जेल के अंदर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही रविवार के दिन गिरिबाला सिंह और समर्थ को जेल के अंदर बात करने का मौका भी दिया गया. दोनों ने इस दौरान एकांत में खड़े होकर बातचीत भी की थी. इस मुलाकात को जेल नियम के अनुसार का बताया गया. रविवार के दिन बंदियों के परिजनों से मुलाकात कराई जाती है .

यह फैसला डीआईजी जेल के निरीक्षण के बाद किया है. सुओं के हवाले से खबर है कि 3 और 4 जून को पूर्व जज गिरिबाला सिंह और

उनके बेटे समर्थ को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का जानकारी सामने आई. डीआईजी जेल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण

डिजिटल शिक्षा की दौड़ में संघर्ष करता एमपी

10 सालों में 41.9 % की वृद्धि हुई इंटरनेट उपलब्धता में 99.5 % का चंडीगढ़ ने किया हासिल

साक्षी केसरवानी भोपाल, 08 जून. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों को कंप्यूटर और इंटरनेट को क्लासरूम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. नीति आयोग की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014-15 में देश भर में केवल 26.42 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर थे. जो आंकड़ा साल 2024-25 में

बढ़कर 64.7 प्रतिशत हो गया है. जिसमें सबसे तेज बढ़त साल 2020-21 के बाद देखी गई. वहीं कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल अब भी बुनियादी डिजिटल ढांचे के लिए संघर्ष कर रहे हैं. देश भर में कंप्यूटर उपलब्धता में लक्षद्वीप ने 100 प्रतिशत, दिल्ली ने 99.9 प्रतिशत, पुडुचेरी ने 99.5 प्रतिशत, चंडीगढ़ ने 99.5 प्रतिशत और केरल ने 99.5 प्रतिशत के साथ करीब सभी स्कूलों तक कंप्यूटर

पहुंचा दिए हैं. इसके उलट मेघालय में सबसे कम 19.7 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 25.1 प्रतिशत और बिहार में 25.2 प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर हैं. हालांकि इस सूची में मध्य प्रदेश ने औसत दर्जे पर काम कर 10 सालों में 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 59.2 प्रतिशत तक ही पहुंच सका है. जिसके अनुसार अब भी करीब 40 प्रतिशत स्कूल प्रदेश में कंप्यूटर के अभाव में डिजिटल शिक्षा से वंचित हो रहे हैं.

मध्यप्रदेश का प्रदर्शन निराशाजनक पिछले 10 सालों में देश भर के 8.05 प्रतिशत स्कूलों से इंटरनेट उपलब्धता बढ़कर 63.5 प्रतिशत स्कूलों में पहुंच चुकी है . जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत के करीब सफलता पाई है. वहीं मध्य प्रदेश के केवल 45.7 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाई है. जो कि साल 2014-15 में 3.8 प्रतिशत स्कूलों में थी. जिसमें 10 सालों में कुल 41.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. लेकिन आज भी करीब 50 प्रतिशत से अधिक स्कूल इंटरनेट की उपलब्धता से वंचित हैं .



अवैध कोडीन युक्त ऑनरेक्स कफ सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार

थाना अमिलिया पुलिस ने की घेराबंदी कार्रवाई

सीधी,8 जून थाना अमिलिया पुलिस ने दबिबन कार्रवाई करते हुए अवैध कोडीन युक्त ऑनरेक्स कफ सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट के मार्गदर्शन में थाना अमिलिया पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की गई है।

पुलिस के अनुसार दिनांक 07 जून 2026 को थाना अमिलिया पुलिस की टीम अपराध विवेचना एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम कोदौरा में मौजूद थी। इसी दौरान विक्ससनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कोडीन फॉस्फेट युक्त ऑनरेक्स कफ सिरप लेकर हनुमना की ओर से हिनौती आ रहा है। सूचना की

तस्दीक करते हुए पुलिस टीम द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ग्राम हरदी स्थित मुड़ा पहाड़ शिव मंदिर के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति विक्रांता मोटरसाइकिल से आता दिखा दिया, जिसे रोककर पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रक्ते बैग से 26 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप (प्रत्येक 100 एमएल) बरामद हुई, जिसमें कोडीन फॉस्फेट पाया गया। आरोपी को 26 शीशी कोडीन युक्त ऑनरेक्स कफ सिरप अनुमानित कीमत10,400 रुपये, विक्रांता मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 53 एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम कोदौरा में मौजूद थी। आरोपी ने रत्नेश सोनी पिता हरप्रसाद सोनी उम्र 29 वर्ष निवासी हिनौती, थाना अमिलिया, जिला सीधी है।